units, including bottling plants for fruit juices/beverages.

दिल्ली में भारत निर्मित अंग्रेजी शराब में मिलावट

2283. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** क्या शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत निर्मित अंग्रेजी शराब के मामले में दिल्ली में कोटि नियंत्रण किस प्रकार लागू किया जाता है ;

(ख) क्या भारत निर्मित अंग्रेजी शराब में देशी शराब मिला कर बेची जा रही है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में कितने छापे मारे गये और कितने लाइसेंस जब्त/रद्द किये गये ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग) . भारत में बनी विदेशी शराब का उत्पादन दिल्ली में नहीं होता है । इसलिए 'कोटि नियन्त्रण" को लागू करने का प्रश्न ही नहीं जहां तक भारत में बनी विदेशी शराब को दिल्ली में लाने का सम्बन्ध है, निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :—

(1) दिल्ली में प्रेषित माल के पहुंचने पर आबकारी पदाधिकारियों द्वारा उसकी जांच की जाती है ।

(2) समय-समय पर नमूने लिए जाते हैं और उनका रसायनिक विश्लेषण किया जाता है ।

(3) नए ब्रांडों की शराब को तब तक बेचने की इजाजत नहीं दी जाती जब तक उनके नमूने विहित किए जाते स्तर के नहीं पाए जाते ।

(4) आबकारी कर्मचारियों द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किए जाते हैं और छापे मारे जाते हैं ।

Funds utilised for minor Irrigation in States

2284. **SHRI RAM PARKASH:** Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) amount granted to different States for minor irrigation schemes during the last and the current financial years;

(b) names of States which have utilised the amounts; and

(c) names of the States which have not used the grants?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SHAHNAWAZ KHAN): (a) Schemes for minor irrigation are included in the State plans. Central assistance for State Plan schemes is given to the State Governments in the form of block loans and grants for the State plan as a whole and the assistance is not linked with any particular head of development or scheme. However, based on the totality of Statewise financial resources, the Planning Commission in consultation with State Governments and Central Ministries make recommendations in regard to sectoral outlays. The amounts recommended by the Planning Commission for minor irrigation in different States during the last year, i.e. 1975-76 and the current year i.e. 1976-77 are given in the statement attached.

(b) and (c). On the basis of the anticipated expenditures reported by the States at the time of the annual plan discussions for 1976-77, all the States except Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, M.P., Punjab and Tamil Nadu will have utilised fully or exceeded the amounts recommended by the Planning Commission during 1975-76. The current financial year has recently started and the position about the utilisation of the outlays would be known only towards the end of the year.